राज्यपाल सचिवालय
राजभवन, जयपुर

गणत्न्त्र दिवस – 2020

गणतन्त्र दिवस पर राज्यपाल की शुभकामनाएं

एकता में ही विकास निहित है – राज्यपाल

जयपुर, 25 जनवरी। राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने 71वें गणतन्त्र दिवस पर प्रदेशवासियों और सीमा पर तैनात जवानों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। राज्यपाल श्री मिश्र ने राष्ट्र की रक्षा में बलिदान करने वाले शहीदों को नमन करते हुए आजादी में योगदान देने वाले स्वतन्त्रता सेनानियों के त्याग, संघर्ष एवं बलिदान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की है।

राज्यपाल श्री मिश्र ने कहा है कि '' हम सभी को अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, गौरवपूर्ण इतिहास और आत्मसम्मान की भावना को संजोये रखकर विकसित एवं सम्पन्न राजस्थान के निर्माण में सक्रिय सहभागिता का संकल्प लेना होगा। राज्यपाल श्री कलराज मिश्र का गणतन्त्र दिवस पर संदेश अविकल रूप से प्रस्तुत है–

- हम आज देश का 71वां गणतन्त्र दिवस बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मना रहे हैं। इस मौके पर मैं सभी भाई–बहनों को हार्दिक बधाई देता हूं। मेरी शुभकामना है कि नया साल आप सभी के लिए मंगलमय एवं सुख–समृद्धि से परिपूर्ण हो।
- सर्वप्रथम मैं ज्ञात–अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं उन स्वतंत्रता सेनानियों को शत्–शत् नमन करता हूं जो आज हमारे बीच मौजूद हैं, मैं उनके स्वस्थ जीवन और दीर्घायु की कामना करता हूं। राष्ट्र की एकता और अखण्डता को बनाये रखने के लिए उन शहादत देने वाले जांबाज सैनिकों, अर्द्धसैनिक बलों के जवानों तथा पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। राजस्थान से जुड़ी अन्तराष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा के लिए तैनात सेना, अर्द्धसैनिक बल एवं पुलिस के जवानों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।
- देश एवं प्रदेश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयन्ती एवं पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्व. श्री राजीव गांधी की 75वीं जयन्ती मना रहा है। लोककल्याणकारी राज्य सरकार बापू के आदर्शों से प्रेरणा लेकर आमजन को सुशासन देने के लिये प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है।
- **महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना** के अन्तर्गत प्रत्येक जिले में एक महात्मा गांधी आदर्श गांव का चयन कर सुनियोजित विकास किया जा रहा है।
- ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर ''महात्मा गांधी ग्रामोत्थान शिविर'' आयोजित किये जाकर पात्र व्यक्तियों को पट्टे जारी कर लाभान्वित किया गया है।
- आम आदमी को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिये निरोगी राजस्थान अभियान शुरू किये जाने के साथ ही **स्वास्थ्य के अधिकार का कानून** बनाये जाने की कार्यवाही की जा रही है। सरकार द्वारा कच्ची बस्ती एवं झुग्गी–झोपड़ी में रहने वाले गरीब नागरिकों को उनके घर के नजदीक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु जनता क्लिनिक खोले जाने की शुरुआत कर दी गयी है।
- कैंसर, किडनी एवं हार्ट जैसी गम्भीर बीमारियों के लिये भी अब निःशुल्क दवाईयां उपलब्ध कराने के साथ ही बी.पी.एल. एवं वरिष्ठ नागरिकों को एम.आर.आई. एवं सीटी स्कैन की सुविधाएं एस.एम.एस. की तर्ज पर 6 अन्य मेडिकल कॉलेज अस्पताल एवं आर.यू.एच.एस. मेडिकल कॉलेज (जयपुरिया अस्पताल) में भी निःशुल्क उपलब्ध करवायी जा रही हैं।
- राज्य के हर जिला मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज खोलने की दिशा में कार्यवाही की जा रही है।
- राज्य में शिक्षा क्षेत्र में गुणात्मक सुधार लाने एवं राजकीय विद्यालयों में आधारभूत सुविधाऐं उपलब्ध कराने के लिये लगभग 1 हजार 582 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये हैं तथा आवश्यकतानुसार विद्यालयों को क्रमोन्नत किया जा रहा है।

- राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयन्ती पर सभी जिला मुख्यालयों पर इसी वर्ष अंग्रेजी माध्यम से संचालित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों की स्थापना प्रारम्भ कर दी गयी है। राज्य सरकार द्वारा संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये नये वरिष्ठ उपाध्याय, उच्च प्राथमिक एवं प्राथमिक विद्यालय प्रारम्भ किये जाने की योजना है।
- राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में नवीन राजकीय महाविद्यालय खोले गये एवं 2 राजकीय कन्या महाविद्यालयों को स्नातकोत्तर स्तर पर क्रमोन्नत किया गया है।
- राज्य के शहरों, गांवों एवं ढाणियों में **स्वच्छ एवं शुद्ध पेयजल** की व्यवस्था करवाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में निःशुल्क पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है। शहरी क्षेत्रों में चालू मीटर वाले घरेलू कनेक्शन पर 15 किलोलीटर मासिक उपभोग तक वाटर चार्ज समाप्त किया गया है।
- विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं पर दिसम्बर, 2019 तक लगभग 2 हजार 45 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है।
- राज्य सरकार द्वारा गत एक वर्ष में विद्युत उत्पादन क्षमता में 838 मेगावॉट की वृद्धि की गयी है। नयी राजस्थान सौर ऊर्जा नीति–2019 व राजस्थान पवन व हाइब्रिड ऊर्जा नीति–2019 जारी की गयी है। राज्य में गत एक वर्ष के दौरान सौर ऊर्जा में 1 हजार 599 मेगावॉट की वृद्धि की गयी है तथा 100 मेगावॉट रूफटॉप सोलर संयन्त्र स्थापित किये गये हैं।
- विद्युत प्रसारण व वितरण तन्त्र को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न श्रेणियों के 310 ग्रिड सब–स्टेशन स्थापित किये गये एवं 1 लाख 27 हजार 910 कृषि कनेक्शन तथा ग्रामीण क्षेत्र में 6 लाख घरेलू कनेक्शन जारी किये गये हैं।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के परिवारों की महिलाओं को सक्षम एवं आत्मनिर्भर बनाने की प्रभावी कार्यवाही की गयी है।
- राज्य में लगातार गिरते भू–जल को रोकने तथा वर्षा जल का अधिकतम संग्रहण, संरक्षण तथा समुचित उपयोग करने हेतु **''राजीव गांधी जल संचय योजना''** प्रारम्भ की गयी है।
- राज्य सरकार कृषकों के हितों के लिये राजस्थान फसली ऋण माफी योजना के अन्तर्गत पात्र कृषकों को राहत प्रदान की गयी है।
- लघु एवं सीमान्त वृद्धजन सम्मान किसान पेंशन योजना को प्रदेशभर में लागू कर 75 वर्ष से कम आयु के किसानों को 750 रुपये प्रतिमाह तथा 75 वर्ष एवं अधिक आयु के किसानों को 1 हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन से लाभान्वित किया जा रहा है।
- आमजन को राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाने हेतु जन सूचना पोर्टल का शुभारम्भ 13 सितम्बर, 2019 को किया गया।
- लोक कल्याणकारी योजनाओं के लाभ आमजन को सरलता, सुगमता एवं पारदर्शी रूप से पहुंचाने के दृष्टिगत **''राजस्थान जन–आधार योजना, 2019''** का शुभारम्भ 18 दिसम्बर, 2019 को किया गया है, जिसमें योजनाओं के नकद लाभ प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से प्रदान किए जा रहे हैं। राज्य के निवासी परिवारों को एक बारीय निःशुल्क जन आधार कार्ड उपलब्ध करवाया जा रहा है।
- राज्य में उद्योगों के विकास एवं निवेश के लिये राजस्थान औद्योगिक विकास नीति, 2019, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना–2019 एवं ''राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापना और प्रवर्तन का सुकरीकरण) अधिनियम, 2019'' लाये गये हैं। अब नवीन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की स्थापना हेतु प्रारम्भिक तीन वर्ष तक उद्यम विभिन्न विभागों की स्वीकृतियों एवं निरीक्षणों से मुक्त रहेगा।
- राज्य में नये उद्यम स्थापित करने तथा वर्तमान उद्यमों के विस्तार, आधुनिकीकरण एवं विविधिकरण के लिए ''मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना'' प्रारम्भ की गयी है, जिसमें उद्यमियों को 10 करोड़ रुपये तक के ऋण पर 5 से 8 प्रतिशत ब्याज अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है।
- राज्य सरकार ने सड़कों पर 7 हजार 325 करोड़ रूपये का व्यय कर 3 हजार 92 किलोमीटर लम्बाई में नवीन सड़कों, 213 किलोमीटर राष्ट्रीय राज मार्ग, 2 हजार 88 किलोमीटर राज्य राज मार्ग का विकास एवं 12 हजार 409 किलोमीटर की ग्रामीण सड़कों के कार्य पूर्ण किये गये हैं।
- बाढ़ से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों, सड़कों, नहरों एवं नालियों की मरम्मत हेतु 176 करोड़ 70 लाख रुपये आवंटित किये गये हैं।
- राज्य में पहली बार 2011 की जनगणना के आधार पर 500 व अधिक आबादी के सड़कों से बिना जुड़े लगभग 1 हजार गांवों को इसी वर्ष सड़कों से जोड़ने का कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है।

- सभी ग्राम पंचायतों पर **वॉल टू वॉल विकास पथ** बनाये जाने हैं, जिसके प्रथम चरण में 182 ग्राम पंचायतों के लिये 142 करोड़ 53 लाख रुपये स्वीकृत किये गये हैं।
- आमजन को बेहतर **परिवहन सुविधा** उपलब्ध कराने के लिये 876 नयी सुपर एक्सप्रेस ब्ल्यू लाइन बसों की खरीद की जा रही हैं एवं 48 इलेक्ट्रिक बसें अनुबन्ध पर लिये जाने के आदेश जारी किये गये हैं।
- वर्तमान सरकार द्वारा उचित मूल्य की दुकानों से राशन वितरण की व्यवस्था को मजबूत, पारदर्शी एवं जवाबदेही बनाया गया है। **साथ ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना** के तहत 2 रुपये के स्थान पर एक रुपया प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं का वितरण करवाकर 1 करोड़ 74 लाख व्यक्तियों को लाभान्वित किया जा रहा है।
- राज्य में ई.डब्ल्यू.एस. के व्यक्तियों हेतु 10 प्रतिशत आरक्षण संबंधित प्रावधानों में जटिलता होने के कारण आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा था, उक्त वर्ग को आरक्षण का लाभ देने के लिये राज्य सरकार ने सम्पत्ति से संबंधित प्रावधानों को विलोपित कर, केवल 8 लाख रुपये अधिकतम वार्षिक आय को ही पात्रता का आधार रखा है।
- अन्य पिछड़ा वर्ग में क्रीमीलेयर की सीमा 2 लाख 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये की गयी है।
- राज्य में 55 वर्ष एवं अधिक किन्तु 60 वर्ष से कम आयु की विधवा, परित्यक्ता एवं तलाकशुदा महिलाओं को दी जाने वाली पेंशन राशि 500 रुपये को बढ़ाकर 750 रुपये की गयी है। वृद्धावस्था पेंशनधारियों की पेंशन में 250 रुपये की वृद्धि की गयी है।
- **अल्पसंख्यक** वर्ग के कल्याण हेतु विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के अन्तर्गत अभ्यर्थियों को लाभान्वित कर राशि सीधे ही विद्यार्थियों के खातों में हस्तान्तरित की जा रही है।
- **जनजाति क्षेत्र** में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सराड़ा (उदयपुर) पीपलखूंट (प्रतापगढ़) में 4 नवीन एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय प्रारम्भ किये गये हैं।
- राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के सशक्तीकरण के उद्देश्य से 1 हजार करोड़ रुपये की **इंदिरा महिला शक्ति निधि** का गठन किया गया है।
- मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना के अन्तर्गत प्रदेश के **बेरोजगार युवकों को प्रतिमाह 3 हजार रुपये एवं युवतियों, दिव्यांग एवं ट्रांसजेण्डर को 3 हजार 500 रुपये** प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ते के रूप में लाभान्वित कर राहत दी जा रही है।
- **राज्य खेल 2020** का अभूतपूर्व आयोजन सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर में 2 से 6 जनवरी 2020 तक किया गया जिसमें 18 खेलों में 8 हजार खिलाड़ियों ने भाग लिया। राज्य के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने हेतु राष्ट्रीय स्तर के खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को राजकीय सेवा में 2 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान का सरलीकरण किया गया है।
- **फसल खराबा एवं टिड्डी प्रभावित कृषकों** को कृषि आदान–अनुदान प्रदान करने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है।
- **पशु चिकित्सा सेवाओं में विस्तार** करने के लिये इस वर्ष 400 नवीन उपकेन्द्र खोले जा रहे हैं।
- उन्नत कृषि तकनीक को सहज एवं सरल तरीके से किसानों तक पहुंचाने के उद्देश्य से एक दिवसीय राज्य स्तरीय **किसान सम्मेलन** का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 28 हजार कृषकों ने भाग लिया।
- **वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना** के अन्तर्गत वरिष्ठ नागरिकों को लाभान्वित किया जा रहा है।
- जनकल्याणकारी सरकार का यह कर्तव्य है कि सभी को न्याय व सुनवाई सुनिश्चित हो। आमजन का पुलिस के प्रति विश्वास बनाये जाने की दिशा में राज्य के थानों में स्वागत केन्द्र स्थापित किये जाकर भयमुक्त वातावरण तैयार किया जा रहा है।
- राज्य में कोई भी व्यक्ति अब निःसंकोच पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करा सकता है। यदि किसी कारणवश थाने में एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है, तो पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एफआईआर दर्ज करवायी जा सकेगी। ऐसी स्थिति में थानाधिकारी की जवाबदेही भी तय की जायेगी। ऐसी व्यवस्था करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है।
- विकास के लिये प्रतिबद्ध संवेदनशील सरकार राज्य के समग्र विकास के लिये हरसंभव प्रयास कर रही है। राज्य सरकार की सकारात्मक एवं दूरदर्शी सोच राज्य को निरंतर विकास की ओर अग्रसर कर रही है, जिसके परिणामस्वरूप राज्य के सर्वांगीण विकास के साथ–साथ प्रदेशवासियों का जीवन स्तर भी पहले से बेहतर हो रहा है।
- अनेकता में एकता भारतीय संस्कृति की विलक्षणता है। हमें सदैव स्मरण रखना है कि हमारा आपसी भाईचारा, सद्भाव और परस्पर स्नेह हमारी एकता को मजबूती देते हैं और विकास के लिए मिलजुल कर कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। एकता में ही विकास निहित है।

- आज का पावन पर्व हमें आत्मनिरीक्षण का अवसर प्रदान करता है। आइये! गणतन्त्र दिवस पर हम सब राजस्थान के ऐतिहासिक गौरव एवं आत्मसम्मान को सर्वोपरि मानकर खुशहाल और समृद्ध नये राजस्थान के निर्माण के लिए मिलजुल कर कार्य करने का संकल्प लें।
- इस पुनीत दिवस पर पुनः मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि आप सभी का जीवन सुख–समृद्धि और उच्च विचारों से आनंदमय हो।

जय हिन्द!

——

राज्यस्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह जयपुर में
राज्यपाल श्री कलराज मिश्र झण्डारोहण करेगे

—

जयपुर, 25 जनवरी। राज्यपाल श्री कलराज मिश्र रविवार 26 जनवरी को गणतन्त्र दिवस के अवसर पर जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में प्रातः 9.30 बजे झण्डारोहण करेंगे। इससे पहले प्रातः 9.00 बजे राजभवन में भी राज्यपाल श्री सिंह झण्डारोहण करेंगे। स्टेडियम में जाने से पहले राज्यपाल श्री सिंह अमर जवान ज्योति पर पुष्पचक्र अर्पित कर अमर शहीदों को नमन कर श्रद्वाजंलि देगे। राज्यपाल श्री मिश्र प्रातः 9 बजे राजभवन मे झण्डारोहण करेंगे और कर्मचारियों को लड्डू वितरित करेंगे।

राज्यपाल के संदेश का प्रसारण रविवार को

—

जयपुर, 25 जनवरी। राज्यपाल श्री कलराज मिश्र गणतंत्र दिवस पर रविवार 26 जनवरी को प्रातः दूरदर्शन और आकाशवाणी से प्रदेशवासियों को संबोधित करेगें। राज्यपाल श्री कलराज मिश्र का प्रदेशवासियों के लिए संदेश का प्रसारण डी.डी. राजस्थान से रविवार 26 जनवरी को प्रातः 8:30 बजे और आकाशवाणी के राज्य के सभी केन्द्रों से प्रातः 7:05 बजे प्रसारित होगा।

राजभवन में होगा एट होम कार्यक्रम

—

जयपुर, 25 जनवरी। गणतन्त्र दिवस पर रविवार को राजभवन में राज्यपाल श्री कलराज मिश्र की तरफ से सांय 4.30 बजे एट होम कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा।

राज्यपाल श्री मिश्र की संवेदना

जयपुर, 25 जनवरी। राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने श्री धनप्रकाश त्यागी के आकस्मिक निधन पर गहरा दुःख व्यक्त किया है। राज्यपाल श्री मिश्र ने दिवगंत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिजनों को इस दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने के लिए परमात्मा से प्रार्थना की है।

———

डॉ. लोकेश चन्द्र शर्मा
सहायक निदेशक (जनसम्पर्क) राज्यपाल